(b) whether it is a fact that he stated that there were some areas in the State where Harijans were not allowed to take water from the common wells and ponds;

(c) if so, which are those areas; and

(d) the steps being taken to remove this difficulty?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): (a) Yes.

(b) No.

(c) and (d). Do not arise.

Irrigation Schemes in Trichur District

4106. Shri A. K. Gopalan: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) how many medium and lift irrigation schemes are in progress in Trichur district, Kerala;

(b) whether the 'Pathazha Kundu' scheme work is at a standstill;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether all these schemes are going to be completed within the scheduled time?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) Work on six medium and two lift irrigation schemes is in progress.

(b) and (c). The work on this scheme has not yet been started due to delay in acquiring the necessary lands. The lands required have not yet been handed over and taken possession of.

(d) The schemes will be completed according to schedule.

महाराष्ट्र में अनुसन्धान योजनाएं

4107. श्री कांबले :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में महाराष्ट्र के लिये कुछ अनुसन्धान योजनाएं मंजूर की गई हैं अथवा की जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—6106/66**]

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय विकास खण्ड

4108. श्री कांबले :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में अब तक जिलावार कितने तथा किन-किन स्थानों पर अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय विकास खण्ड खोले गये हैं तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में जिलावार ऐसे कितने खण्ड खोलने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चव्हाण) : अनुसूचित जातियों के लिये कोई विकास खण्ड नहीं खोले गये हैं । अब तक खोले गये खण्डों तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा खोले जाने वाले प्रस्तावित खण्डों की एक सूची सभा पटल पर रखी गई है [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०—6107/66**]

महाराष्ट्र में ग्रामोद्योग परियोजनाएं

4109. श्री कांबले :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की ग्रामोद्योग आयोजन समिति द्वारा तैयार किये गए ग्रामोद्योग परियोजना सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये महाराष्ट्र के कौन कौन से क्षेत्र चुने गये हैं;

(ख) इन क्षेत्रों का चयन किस आधार पर किया गया है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ख). 1962-63 के दौरान महाराष्ट्र में ग्रामोद्योग परियोजनाओं के सम्बन्ध में चार क्षेत्र यानी जिला वार्धा में वार्धा, जिला अहमदाबाद में संगमनेर, जिला अोसमानाबाद में लतूर और जिला रत्नागिरी में वेंगुर्ला चुने गये । इसके बाद कोई नया क्षेत्र नहीं चुना गया है ।

2. इन क्षेत्रों की चुनाव की कसौटी व्यापक रूप से निम्न प्रकार ह :

(i) काफी बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी का विद्यमान होना;

(ii) प्रतिकूल स्थिति होने के कारण, कृषि क्षेत्र में शीघ्र विकास की सीमित समानताएं होना; और

(iii) क्षेत्रों में लघु-उद्योग और ग्रामोद्योग के विकास के लिए क्षमता विद्यमान होना ।

3. चारों क्षेत्रों का प्रगति प्रतिवेदन, सभा पटल पर रखे गये अनुबन्ध 1 में दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया तारांकित संख्या एल० टी०—6108/66]।

गांवों में वाणिज्यिक बैंक

4110. **श्री कांबले :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री बसवन्त :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गांवों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक बैंक खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक खण्ड मुख्यालय में वाणिज्यिक बैंक स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे अपनी शाखाएं खोलने के कार्यक्रम, देहाती और अर्ध-देहाती क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रख कर बनायें, लेकिन गांवों या विकास खण्डों के सदर-मुकामों में बैंकों की शाखाएं खोलने के कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं ।

(ग) विचार है कि प्रयोग के तौर पर, कुछ चुने हुए केन्द्रों में भारतीय राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले कार्यालय (वन मैन आफिस) और प्रारम्भिक देहाती केन्द्र (रूरल पायलट सेंटर) खोले जायें, और सहकारी केन्द्रीय बैंकों और प्राथमिक ऋण समितियों को, जहां तक हो सके, उन इलाकों में कार्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय जहां वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं नहीं हैं ।

Slum Clearance in Kerala

4111. Shri P. Kunhan: Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the total areas where the slum clearance works have been completed in the various towns of Kerala so far;

(b) the amount that has been provided for this purpose;

(c) whether Government are aware that the Changel Chula Colony in Trivandrum where more than five hunred Harijan families live, has not yet been cleared; and